सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 11 ● अंक: 298 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शनिवार 6 दिसम्बर, 2025
मूल्य ₹ 3/-

मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे-धीरे दुनिया आपको सुनेगी।
-महात्मा गांधी

आईसीसी ह्वश्वलेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए... 7 | संचार साथी ऐप गिद्ध दृष्टि, घर-घर... 3 | संसद में संविधान की रक्षा पर... 2

कंपनी जीती, सरकार हारी, कुचले गये यात्री

एबीसी-एयरलाइन ब्लैकमेल कंट्रोवर्सी से थमी उड़ान

» सरकार ने घुटने टेके वापस लिये नये नियम

» क्या यही चाहती थी विमानन कंपनी

» अगर नियम होते लागू तो कंपनी को होता करोड़ों का नुकसान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बढ़ते हवाई हादसों के बीच सरकार ने हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम बना कर हवाई कंपनियों को निर्देश दिये थे। इन नियमों में कू मेंबर्स और पायलट को नियमित आराम दिये जाने की बात कही गयी थी। उनके रेस्ट को लीव में बदलने की परंपरा को खत्म कर दिया गया था। यह नियम 25 नवम्बर से लागू हुए थे और इन नियमों के चलते एयर कंपनियों को नुकसान हो रहा था। बस यही से आज की हवाई यात्रा में हो रही दिक्कतों की कहानी की शुरूआत होती है।

यह क्राइसस रूटीन क्राइसेस नहीं है बल्कि फैब्रीकेटेड और स्क्रिपटेड क्राइसेस है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सनसनीखेज आरोप सरकार पर लगाये हैं और सरकार की हवाई नीतियों की धज्जियां उड़ा दी है। उनका कहना है कि घरेलू एविएशन इंडस्ट्री को किसी एक कंपनी के हवाले करके सरकार ने बड़ी गलती कर दी। जब देश में चुनावी रणनीतियों और मास्टर स्ट्रोकों की परफार्मेंस चल रही थी ठीक उसी वक्त आसमान में एक और खेल खेला जा रहा था। एविएशन इंडस्ट्री का ब्लैकमेल गेम हवाई यात्राएं वैसे तो सपनों, बिजनेस और टूरिज्म को जोड़ने के लिए होती हैं। लेकिन इन दिनों देश के लाखों यात्रियों ने जाना कि उड़ान भरना अब सपने से ज्यादा किसी बेबस व्यवस्था के आगे हाथ जोड़ने जैसा हो गया है।

नुकसान टिकट से ज्यादा भरोसे का

जो लोग आठ से दस हजार के बीच टिकट लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हो उनसे पूछिये कि उन्हें कितनी पीड़ा हुई। रद्द उड़ान सिर्फ एक यात्रा का टूटना नहीं होती। इस पूरे परिदृश्य में किसी का जाब इंटरव्यू छूट गया। कोई मरीज अपने डॉक्टर तक नहीं पहुच सका। कोई परिवार अपने इकलौते बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया लेकिन एयरलाइन का संदेश असुविधा के लिए खेद है जैसे कोई चाय गिर गयी हो। यह खेद कभी नुकसान नहीं भरता लेकिन क्राइसिस बनाकर नियम जरूर बदलवा देता है।

फैब्रिकेटेड क्राइसिस आपरेशन ब्लैकमेल

जैसे ही नये नियम लागू हुए फ्लाइट कैंसल होना शुरू हो गयी। फ्लाइट डिले होना शुरू हो गयी और क्रू मिसमैच भी शुरू यही नहीं तेजी से रूट आपरेशन रद्द हुए। और यात्रियों को ऐसा संदेश जाने लगा कि देखे सुरक्षा के नाम पर सरकार ने जो नए नियम लगाए हैं उसी से यह संकट आया

है। माहौल ऐसा बनाया गया जैसे एयरलाइंस कह रही हों नियम हटाओ नहीं तो फ्लाइट्स बंद। बस यही वह मोड़ था जहां से इस क्राइसिस को नाम मिला एयरलाइन ब्लैकमेल कंट्रोवर्सी।

25 नवम्बर से लागू हुए नियमे के चलते एयर कंपनियों को नुकसान हो रहा था।

पवन खेड़ा की एंट्री से कहानी में विस्फोट

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार से सवाल पूछा है कि सरकार ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को जानबूझकर एक कंपनी के हवाले क्यों किया। जब पूरा मार्केट एक ही पेशेवर घराने के नियंत्रण में होगा तो ऐसे ब्लैकमेल होना स्वाभाविक है। फ्लाइट कैंसल किसी क्राइसिस के कारण नहीं बल्कि मुनाफे के लिए सुनियोजित दबाव बनाया गया था। उनका दावा है कि अगर नियम लागू रहते तो एयरलाइन को करोड़ों का नुकसान होता। और इस नुकसान से बचने के लिए यात्रियों को मोहरा बनाया गया। सरकार ने झुककर साबित किया कि पालिसी नहीं कंपनी ही असली नियामक है, और सोशल मीडिया पर एक ही प्रश्न ट्रेंड करने लगा कि देश चल रहा है या कंपनी?

असली कहानी खेद नहीं खेल है

एक-दो नहीं, दर्जनों नहीं सैकड़ों फ्लाइट्स मतलब हजारों परिवार और करोड़ों के टिकट कैंसिल हुए। इन सबके बीच एयरलाइन कंपनी ने बस एक ही लाइन कही और पढ़ी वह थी असुविधा के लिए खेद है। लेकिन असली कहानी खेद नहीं खेल थी। नये नियमों के तहत देश में पहली बार हवाई यात्रियों की सुरक्षा और कर्मचारियों की सेहत को प्राथमिकता दी गयी थी। लेकिन बस यहीं से संघर्ष शुरू हो गया। कंपनियों के हिसाब से मामला सुरक्षा का नहीं नुकसान का था। आराम बढ़ेगा रोस्टर बिगड़ेगा फलाइट कम होंगी और मुनाफा घटेगा। और जितना मुनाफा घटेगा उतनी नैतिकता और नीति उड़कर बादलों में खो जाएगी।

सरकार फिर पीछे हटी

एयरलाइन के इस हल्के से झटके में ही सरकार हिल गयी। बजाए इसके कि सरकार यात्रियों के लिए कोई बैकअप प्लान तैयार करती। उन्हें उनके गंत्वय तक पहुंचाती। ऐसा कुछ नहीं हुआं। यात्री एयरपोर्ट पर पिसते रहे। किसी का इंटरव्यू छूटा तो कोई किसी अपने का अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। एक ही झटके में हड़कंप मच गया। सरकार एक्शन मोड में तब आई जब सोशल मीडिया पर यात्रियों के गुस्से वाले वीडियो वायरल होने लगे। इन सबके आगे सरकार बेबस दिखी और उसने उन नियमों को वापस ले लिया जो कंपनी चाहती थी। सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। कोई कड़ा बयान नहीं। कोई जुर्माना नहीं। सरकार ने कंपनी से यह तक नहीं पूछा कि फ्लाइट कैंसल कर यात्रियों को किस अधिकार से परेशान किया गया, तस्वीर साफ थी कि कंपनी जीती, सरकार हारी, यात्री कुचले गये।

संसद में संविधान की रक्षा पर बहस होना लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत : अखिलेश

सपा मुखिया ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. अम्बेडकर को किया याद

बोले- देश को मन-विधान से नहीं, संविधान से चलना चाहिए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चेताया कि संसद में संविधान की रक्षा पर बहस होना लोकतंत्र के लिए दुखद संकेत है और यह स्थिति बताती है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार (6 दिसंबर) को डॉ बीआर अम्बेडकर की पुण्यतिथि और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक मजबूत राजनीतिक संदेश जारी किया है. इस संदेश में उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश का नारा 'जय जवान, जय किसान, जय संविधान' होना चाहिए।

अखिलेश यादव ने साफ कहा कि संविधान सिर्फ किताब नहीं, बल्कि देश की बुनियाद है और इसका कमजोर होना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, वे एकतंत्र की ओर देश को धकेलना चाहते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि संविधान जनता को अधिकार देता है और जो ताकतें लोगों के अधिकार छीनना चाहती हैं, वे संविधान विरोधी हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान ही लोकतंत्र का कर्म ग्रंथ है और इसलिए इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहराया कि देश को 'मन-विधान' से नहीं, बल्कि संविधान से चलना चाहिए क्योंकि यही देश की दिशा और दशा तय करता है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र की प्राणवायु संविधान को कमजोर कर शासन करने की कोशिश करने वालों के लिए 'आजादी का अमृतकाल' भी केवल एक जुमला है. उन्होंने लोगों से अपील की कि संविधान बचाने के लिए एक और 'करो या मरो' आंदोलन की जरूरत है क्योंकि अगर संविधान बचेगा तो ही न्याय बचेगा। उन्होंने कहा कि जब न्याय सुरक्षित होगा, तभी सभी नागरिकों को बराबरी का सम्मान और मौके मिलेंगे, भेदभाव मिटेगा और समाज में वास्तविक समानता स्थापित होगी। अखिलेश यादव ने अपने संदेश को 'सबको स्थान – सबको सम्मान' के आह्वान के साथ समाप्त किया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की रक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया।

संविधान ही पीडीए समाज का प्रकाश स्तंभ

उन्होंने आगे लिखा कि संविधान ही पीडीए समाज का प्रकाश स्तंभ है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है. उनका कहना था कि संविधान 90त्न शोषित, वंचित, उपेक्षित और पीड़ित जनता का सच्चा संरक्षक है। उन्होंने इसे राष्ट्र का रक्षा कवच, ढाल और सबसे बड़ा मददगार बताते हुए कहा कि संविधान है तो ही सुरक्षा और शक्ति है। अखिलेश ने बार-बार दोहराया कि पीडीए के लिए संविधान बचाना जीवन-मरण का विषय है और जो लोग संविधान नहीं मानते, उनके लिए यह सिर्फ एक कोरा पन्ना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान को निष्क्रिय करना स्वतंत्रता को निष्क्रिय करने जैसा है।

भाजपा के लोग कैसे कर रहे घुसपैठियों की जांच

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में घुसपैठिये नहीं हैं। घुसपैठियों की जांच भाजपाई कर रहे हैं। उन्हें किसने यह अधिकार दिया। लखनऊ के सांसद ही रक्षामंत्री हैं। घुसपैठिये यहां बस गए तो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री क्या कर रहे थे। यहां गरीब लोगों को अपमानित और परेशान किया जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आज बुलडोजर कहां है। बुलडोजर सिर्फ पीडीए पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर रूस के राष्ट्रपति आए हैं तो वह कारोबार करने आए हैं, हमारी मदद नहीं लेंगी।

एसआईआर भाजपा सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए करा रही

अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर भाजपा सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए करा रही है। हमारी अपील है कि सब अपना वोट बनवाएं, कटने से बचाएं, वरना भाजपा बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान के अधिकार को छीनने की तैयारी में है। वोट का अधिकार छिना तो आरक्षण भी खत्म होगा। जनता के तमाम दूसरे अधिकार जो संविधान से मिल रहे हैं, वे भी छिन जाएंगे।

नेहा सिंह राठौर को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने अर्जी खारिज की

पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पर टिप्पणी मामले में राहत नहीं मिली। कोर्ट ने नेहा के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज केस में उन्हें अग्रिम जमानत मंजूर करने के आग्रह वाली अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले बीते 19 सितंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नेहा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू-मुस्लिम राजनीति से जुड़े अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज इसी एफआईआर को रद्द करने का आग्रह किया था।

न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया। इसमें, नेहा ने केस में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की गुजारिश की थी। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए शासकीय अधिवक्ता डा वी के सिंह

का कहना था कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में अप्रैल में एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ, जब उन्होंने एक्स (एक्स) पर पोस्ट किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी बिहार आए ताकि पाकिस्तान को धमका सकें और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सकें। उन्होंने यह भी लिखा था कि आतंकियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि बीते 19 सितंबर को खंडपीठ ने नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज करके उनको 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में संज्ञेय अपराध दर्शाते हैं, जिनकी पुलिस द्वारा जांच की जानी उचित है। अदालत ने कहा था कि उनके ट्वीट्स का समय बेहद अहम है, क्योंकि वे पहलगाम हमले के तुरंत बाद पोस्ट किए गए थे। ऐसे में इसी मामले में नेहा की अग्रिम जमानत मंजूर होने योग्य नहीं है। एकल पीठ ने कहा कि यह अग्रिम जमानत का मामला नहीं बनता है, लिहाजा अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

देश का नागर विमानन क्षेत्र 'पैरालिसिस' जैसी स्थिति में

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश नागर विमानन क्षेत्र 'पैरालिसिस' जैसी स्थिति में है और केंद्र सरकार को हालात सामान्य करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''देश में नागर विमानन क्षेत्र इस वक्त 'पैरालिसिस' (निष्क्रियता) जैसी स्थिति में आ गया है। पूरे देश में हवाई यात्री परेशान हैं और बेबस महसूस कर रहे हैं। उड़ानें रद्द हो रही हैं, तो कहीं बच्चे भूखे और थके हुए हैं, महिलाएं, वृद्ध, बीमार लोग लाचार महसूस कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विमानन क्षेत्र में जारी गड़बड़ियों के संबंध में लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज सरकार की इस लापरवाही का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। उन्होंने लिखा, ''केंद्र सरकार को अपने तमाम संसाधन लगा कर स्थिति को सामान्य करने की ओर अविलंब ध्यान देना चाहिए एवं स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

हरियाणा में भर्ती में अनियमितता हुई : चौटाला

इनेलो के अध्यक्ष बोले- आरक्षित सीटें खाली छोड़ने की साजिश हुई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। इनेलो के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने एचपीएससी की हालिया भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार पर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर के 613 पदों के लिए ली गई परीक्षा में 2200 उम्मीदवार शामिल हुए थे लेकिन केवल 151 ही न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक हासिल कर पाए।

डीएससी के 60 पदों पर सिर्फ 1 अभ्यर्थी पास हुआ, ओएससी के 60 में से 2, बीसीए के 85 में से 3, बीसीबी के 36 में से 5, ईडब्ल्यूएस के 60 में से 6 और जनरल कैटेगरी के 312 पदों पर केवल 134 उम्मीदवार ही उत्तीर्ण हुए। कहा, यह पूरा खेल बाहरी राज्यों के लोगों

को हरियाणा की सरकारी नौकरियों में समायोजित करने का षड्यंत्र है।

हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से दो दिन पहले घोषित अंग्रेजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के विषय ज्ञान परीक्षा के घोषित परिणाम पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। पंचकूला स्थित आयोग के मुख्यालय में विभिन्न जिलों व दूसरे राज्यों से अभ्यर्थी पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उत्तीर्ण होने के लिए जो 35 प्रतिशत लाने की अनिवार्यता थी जिनमें केवल 151 ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकरण में निष्पक्षता से जांच की मांग को लेकर मुख्यालय पर पहुंचकर अभ्यर्थियों ने मुख्यालय के बाहर परिसर में लेट गए और हाथ जोड़कर न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। यह भी चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिला तो कोर्ट जाएंगे।

विभिन्न जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा से मुलाकात की मांग की लेकिन देरी को लेकर अभ्यर्थी भड़क गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों की नाराजगी तो देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा।

संचार साथी पर सियासी हाहाकार

विपक्ष के निशाने पर आई सरकार, नेता बोले- तानाशाही का नया रूप

» आप-सपा व कांग्रेस ने किया प्रहार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। मोदी सरकार बीच-बीच में ऐसी व्यवस्था लाती रहती है जिससे सियासी संग्राम मच जाता है। फिर जब विपक्ष उस पर हमला करता है तो वह बैकफुट पर चली जाती है। इस तरह वह किसान कानून में पीछे हट गई थी। ताजा मामला संचार ऐप को लेकर है। जिसको लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है। मामले को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम मचा रहा। हालांकि विवाद ज्यादा बढ़ने पर कें द्रीय मंत्री ज्योर्तिदित्य सिंधिया ने कहा कि यह वैकल्पिक जो नहीं चाहता है वह फोन से उसे डिलीट कर सकता है।

आप व कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर भाजपा सरकार पर जासूसी को आरोपा लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने संचार सारथी ऐप को अनिवार्य किए जाने पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है, जिसे वे व्यक्तिगत निजता और स्वतंत्रता पर सीधा हमला बता रहे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे स्वैच्छिक बताया है। कई विपक्षी सदस्यों ने इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि इससे सरकारी निगरानी और व्यक्तिगत संचार में घुसपैठ की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार के अनुसार, यह ऐप केवल उपयोगकर्ताओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाने, दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की रिपोर्ट करने में उनकी सहायता करने और साइबर अपराध से निपटने में सार्वजनिक भागीदारी या जनभागीदारी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है।

बयान के अनुसार कि सिर्फ पिछले एक दिन में, छह लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण कराया है। यह इसके उपयोग में 10 गुना वृद्धि है। संचार साथी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने मोबाइल विनिर्माताओं के लिए इसे पहले से 'इंस्टॉल' करना अनिवार्य नहीं करने का फैसला किया है। दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर के आदेश में, स्मार्टफोन विनिर्माताओं को सभी नए मोबाइल फोन में ऐप को पहले से लगाने और पुराने मोबाइल फोन में इसे अद्यतन करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेताओं ने इससे जासूसी की चिंता जताई। उनका कहना है कि यह ऐप कॉल सुन सकता है और संदेशों की निगरानी कर सकता है।

निजता और स्वतंत्रता पर एक स्पष्ट हमला : तहसीन

राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने इस जनादेश को निजता और स्वतंत्रता पर एक स्पष्ट हमला बताया। इस कदम का बचाव करते हुए, भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि निजता को कोई खतरा नहीं है और सभी डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे। त्रिपाठी ने कहा, मैं आईआईटी से हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह के साइबर हमले हो रहे हैं... हमारा डेटा बच नहीं पाएगा, और नागरिक सुरक्षा के हर पहलू को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।

ऐप को सक्रिय करना पूरी तरह से स्वैच्छिक : ज्योतिरादित्य सिंधिया

इससे पहले आज, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि मोबाइल उपकरणों पर संचार साथी ऐप को सक्रिय करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उपयोगकर्ता किसी भी अन्य एप्लिकेशन की तरह, किसी भी समय ऐप का उपयोग करने या इसे हटाने का विकल्प चुन सकते हैं। सिंधिया ने स्पष्ट किया कि संचार साथी एप्लिकेशन उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है, उन्होंने दोहराया कि न तो इसे इंस्टॉल करना और न ही सक्रिय करना अनिवार्य है। संसद के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि उपयोगकर्ताओं को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है; जो लोग ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते, वे पंजीकरण न कराने के लिए स्वतंत्र हैं, और वे इसे किसी भी समय हटा भी सकते हैं। मंत्री ने कहा कि यदि आप इसे सक्रिय करना चाहते हैं, तो करें। यदि आप इसे सक्रिय नहीं करना चाहते, तो न करें। यदि आप चाहें तो इसे हटा दें। यह पूरी तरह से आपकी पसंद है। सिंधिया ने ज़ोर देकर कहा कि गलत सूचना ऐप के उपभोक्ता-संरक्षण लाभों पर हावी नहीं होनी चाहिए, और कहा कि इस प्लेटफॉर्म ने 2024 में 22,800 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में योगदान दिया है।

संचार साथी क्या है?

तो, ये सारा हंगामा किस बात को लेकर है? दरअसल, संचार साथी ऐप को लेकर है जिसे अब भारत के सभी स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम नागरिकों को नकली हैंडसेट खरीदने से बचाने के लिए जरूरी है। दूरसंचार विभाग साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संचार साथी पहल शुरू कर रहा है। दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल और ऐप विकसित किया है, जो नागरिकों को आईईएमआई नंबर के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की जांच करने में सक्षम बनाता है, साथ ही अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है जैसे संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार, खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करना, अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जाँच करना, और बैंकों या वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय संपर्क विवरण। दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या वाले दूरसंचार उपकरणों के निर्माताओं को छेड़छाड़ किए गए दूरसंचार उपकरणों आईईएमआई नंबरों के संबंध में आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। नियमों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि ऐसे निर्माता या आयातक नियमों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जा सकने वाले निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1.4 अरब लोगों के लिए टखने पर मॉनिटर, कॉलर और ब्रेन इम्प्लांट : जॉन ब्रिटास

सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा,अगला कदम ज़ाहिर है। 1.4 अरब लोगों के लिए टखने पर मॉनिटर, कॉलर और ब्रेन इम्प्लांट। तभी सरकार को पता चलेगा कि हम असल में क्या सोचते और करते हैं।

संचार साथी ऐप गिद्ध दृष्टि, घर-घर की जासूसी का प्रयास : अखिलेश

सपा सांसद अखिलेश यादव ने संचार साथी ऐप को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार नागरिकों की निजता पर गिद्ध जैसी नजर रख रही है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद अब आपसी बातचीत की गोपनीयता भी खतरे में है। समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मोबाइल हेडसेट पर संचार साथी ऐप को सक्रिय करने के निर्देश को लेकर तीखा राजनीतिक हमला बोला और दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी अब नागरिकों के निजी स्थानों पर भी निगरानी बढ़ा रही है। एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है, बल्कि लोगों के घरों और परिवारों के अंदर की बातचीत की गोपनीयता भी खतरे में है। यादव की पोस्ट में लिखा है कि जिनका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो वो जासूसी करना कैसे छोड़ सकते हैं। भाजपा सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी तो पहले ही छिनी जा रही थी अब घर-परिवार, नाते-रिश्तेदार, मित्रता-कारोबार की आपसी बातचीत पर भी भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों की गिद्ध निगाह लग जाएगी। अब जनता ने फ़ैसला कर लिया है भाजपा सरकार नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि भाजपा जाए तो निजता बच पाए!

केंद्र का ऐप निर्देश व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला : केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मोदी सरकार के उस निर्देश की कड़ी आलोचना की, जिसमें सभी मोबाइल निर्माताओं को नए और मौजूदा फोन में संचार सारथी ऐप पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत निजता और स्वतंत्रता पर सरासर हमला बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अधिसूचना में न तो उपयोगकर्ता की सहमति मांगी गई है और न ही ऐप को अनइंस्टॉल करने का विकल्प दिया गया है। उन्होंने इसे घोर तानाशाही कार्रवाई बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार द्वारा सभी मोबाइल निर्माताओं को सभी नए और मौजूदा फोन में संचार सारथी ऐप इंस्टॉल करने का आदेश व्यक्तिगत निजता और स्वतंत्रता पर एक बेशर्म हमला है। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र ने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में ऐप इंस्टॉल करने के लिए व्यक्तिगत सहमति लेने या इसे किसी भी समय हटाने का विकल्प देने का कोई उल्लेख नहीं है। आम आदमी पार्टी इस तरह की घोर तानाशाही कार्रवाई की निंदा करती है और अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग करती है।

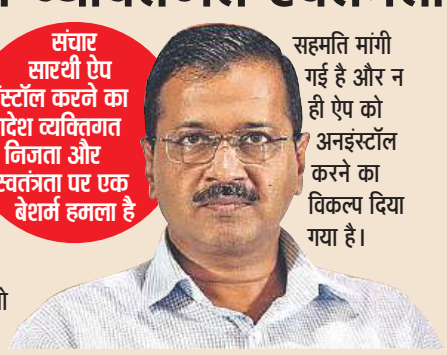

यह पेगासस प्लस प्लस : कार्ति चिदंबरम

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने लिखा, यह पेगासस प्लस प्लस है। बिग ब्रदर हमारे फोन और लगभग पूरी निजी जिंदगी पर कब्जा कर लेगा। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा,भारत सरकार द्वारा हर मोबाइल निर्माता कंपनी को संचार साथी मोबाइल एप्लिकेशन को एक स्थायी मोबाइल फीचर के रूप में अनिवार्य करना, एक और बिग बॉस निगरानी का मामला है।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

हंगामें की भेंट न चढ़े संसद सत्र

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुए पांच दिन हो गए । पर अब तक कोई सार्थक बहस नहीं हो पाई। एसआईआर जैसे मुद्दे को लेकर विपक्ष व सता पक्ष में टकराव हो रहा है। हालांकि इस पर चर्चा के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उस दिन सार्थक सत्र रहेगा । पर अभी जिस तरह से संसद के दोनों सदनों में देखने को मिल रहा उससे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पक्ष गैर जिम्मेदाराना परिचय दे रहे हैं। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरना और सवाल उठाना। लेकिन, दोनों को सदन की मर्यादा और कार्यवाही की अहमियत को ध्यान में रखना होगा। अगर देश के जनप्रतिनिधि पिछले सत्र से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। यह तो साफ हो गया है और विपक्ष ने अपने मुद्दे साफ कर दिए हैं। मॉनसून सेशन अगर ऑपरेशन सिंदूर के नाम था, तो इस बार बहस के केंद्र में एसआईआर है लेकिन, सरकार और विपक्ष - दोनों से ही सदन के भीतर ज्यादा समझदारी, संयम और सहयोग की अपेक्षा है, ताकि सत्र में अधिक काम हो सके।

शीत सत्र एक से 19 दिसंबर तक चलना है। इसमें कुल 15 दिन कार्यवाही चलेगी और इस दौरान शिक्षा, सड़क और कॉरपोरेट लॉ संबंधी कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। इसी सत्र में हेल्थ सिक्योरिटी एंड नैशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 भी रखा जा सकता है, जिसका मकसद देश के हेल्थ ढांचे और सुरक्षा तैयारियों के लिए एक नया उपकर लगाना है। इसके साथ विपक्ष की भी अपनी मांगें हैं, जिसे सर्वदलीय बैठक में रखा गया। विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, एसआईआर वायु प्रदूषण और विदेश नीति पर विस्तृत चर्चा चाहता है। अच्छी बात है कि विपक्षी दलों ने इस बारे में पहले ही अवगत करा दिया है और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के ही मुताबिक, किसी ने भी यह नहीं कहा कि संसद नहीं चलने दी जाएगी। सरकार और विपक्ष, दोनों का इस पर सहमत होना कि सदन चलना चाहिए, स्वागत योग्य है। लेकिन, कमोबेश इसी तरह की सहमति हर बार सेशन शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठकों में दिखती है और कार्यवाही शुरू होने के बाद राजनीति हावी हो जाती है। बीता हुआ मॉनसून सत्र इसका उदाहरण है, जब लोकसभा की प्रॉडक्टिविटी महज 31प्रतिशत के आसपास और राज्यसभा की लगभग प्रतिशत रही। हंगामे और शोर-शराबे की वजह से दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण घंटे बर्बाद हो गए थे। इस बार भी सदन के बाहर की सियासी स्थिति तनाव भरी है। 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर को लेकर विपक्ष की आपत्तियों की लिस्ट लंबी है। वह लगातार इस प्रक्रिया के औचित्य और पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। इसे लेकर दोनों सदनों में भी भिड़ंत देखने को मिल सकती है, लेकिन यह दोनों पक्षों को समझना होगा कि हंगामेबाजी से किसी सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे।

सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरना और सवाल उठाना। लेकिन, दोनों को सदन की मर्यादा और कार्यवाही की अहमियत को ध्यान में रखना होगा। अगर देश के जनप्रतिनिधि पिछले सत्र से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

अमेरिकी दबाव के बावजूद परवान चढ़ती दोस्ती

पुष्परंजन

इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 4 दिसंबर को दो दिन के वास्ते स्टेट विजिट पर आना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। फरवरी, 2022 में यूक्रेन में युद्ध आरंभ होने के बाद से पुतिन का यह पहला आधिकारिक आगमन होगा। पुतिन, पिछली बार यूक्रेन युद्ध से कुछ माह पहले, दिसंबर 2021 में भारत आए थे। रूसी राष्ट्रपति का रेड-कार्पेट वेलकम साउथ ब्लॉक में किया जाएगा, जहां 23वीं सालाना इंडिया-रूस शिखर बैठक होगी। भारत और रूस के बीच 'स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' है, जिसके तहत एसयू-57 फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस शील्ड एस-500 के एडवांस्ड वर्शन की खरीद पर बातचीत होने की उम्मीद है। यह समझौता अमेरिका के साथ किसी भी ट्रेड डील को मुश्किल बना सकता है, जिसने मॉस्को से भारत के हथियारों की खरीद को पीछे धकेल दिया है।

ठीक से देखा जाये, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति संतुलन सिद्धांत को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाये रखना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप का हठयोग इस मार्ग में बाधा पैदा कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में खत्म होने वाले चार सालों में रूसी हथियारों की खरीद में काफी गिरावट के बावजूद मॉस्को भारत का सबसे बड़ा मिलिटरी हार्डवेयर सप्लायर बना हुआ है। भारत के पास 200 से ज्यादा रूसी फाइटर जेट और एस-400 डिफेंस शील्ड की कई बैटरी हैं, जिनका इस्तेमाल मई में पाकिस्तान के साथ चार दिन की लड़ाई के दौरान किया गया था। रक्षा मंत्रालय के सूत्र बताते हैं, कि भारत की सेना के पास फाइटर जेट की कमी है, और सरकार से इस कमी को पूरा करने के लिए रूस निर्मित एडवांस्ड फाइटर जेट खरीदने का आग्रह किया है। सूत्र यह भी बताते हैं, कि एसयू -57 जेट में लगी लंबी दूरी की मिसाइलें दक्षिण एशियाई देश को ज्यादा विजुअल रेंज कैपेबिलिटी देंगी। हालांकि, रूस-भारत के बीच हुए समझौते को स्टेट ड्यूमा में मंजूरी मिलनी बाकी है।

दो दिन की शिखर बैठक में, दोनों पक्ष डिफेंस कोऑपरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन, स्पेस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर चर्चा करेंगे। चेन्नई स्थित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर एनआर भानुमूर्ति के मुताबिक, भारत के लिए 93 मिलियन डॉलर के हथियारों के सौदे को वॉशिंगटन की मंजूरी, महीनों के ट्रेड टेंशन के बाद दोनों पक्षों के बीच रिश्तों

में सुधार का संकेत है, और यह अगले साल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नई दिल्ली दौरे की संभावित शुरुआत भी है। यूक्रेन शांति समझौते को आगे बढ़ाने के लिए एक हाई पावर्ड अमेरिकी डेलीगेशन मॉस्को में है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दूत नाम स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर इस हफ्ते डील की कोशिश के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में भारत पर शुरू में 25 प्रतिशत इंपोर्ट टैरिफ लगाया था, फिर इसे बढ़ाकर 50 फीसद कर दिया। यह टैरिफ दिल्ली द्वारा रूसी तेल खरीदने पर पेनल्टी थी। उन्होंने कहा कि यह तेल खरीद यूक्रेन से युद्ध के वास्ते मॉस्को को आर्थिक मजबूती दे रही थी। चेन्नई स्थित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर एनआर भानुमूर्ति मानते हैं कि कई भारतीय तेल कंपनियों ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, इसलिए आने वाले हफ्तों में भारत पर अमेरिकी टैरिफ कम होने की संभावना है। उनके बरक्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में इंस्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के सीनियर रिसर्च फेलो अमितेंदु पालित का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है, इसका असर सिर्फ जुलाई-सितंबर वाली तिमाही में महसूस हुआ। अमितेंदु ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड संबंध हाल ही में बेहतर हुए हैं। पिछले महीने अमेरिका से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस खरीदने के लिए सरकारी भारतीय तेल कंपनियों द्वारा साइन किए गए एक साल के अनुबंध पर गौर करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो तर्क अमितेंदु दे रहे हों, उसके आधार पर मान लें कि सब कुछ सही ट्रैक पर चल रहा है। आईएमएफ के जरिये भी अमेरिकी प्रशासन मोदी सरकार पर दबाव बनाये हुए है।

आईएमएफ ने पिछले हफ्ते भारत के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया था। यह बताया गया कि आईएमएफ को दी गई जानकारी में 'कुछ कमियां थीं जो कुछ हद तक सर्विलांस में रुकावट डालती हैं'। तो क्या आईएमएफ की शंकाओं को दूर करने के लिए भारत के इकोनॉमिक डेटा में बदलाव किए जाने की संभावना है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 'क्रेमलिन लॉन्ड्रोमैट' कहा और भारतीय इम्पोर्ट पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी। भारत और पाकिस्तान के बीच बीच-बचाव करने की उनकी लगातार दावेदारी ने भी भारतीय रणनीति के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं।

भरोसा जीतकर हो सुरक्षा उपायों पर अमल

प्रमोद जोशी

दूरसंचार विभाग ने स्मार्टफोन कंपनियों को 'संचार साथी' एप्लीकेशन को अनिवार्य रूप से प्री-लोड करने के अपना आदेश वापस लेकर अच्छा काम किया है। इसे लागू करने का बेहतर तरीका यही था कि लोगों पर छोड़ दिया जाता कि वे चाहें, तो इसे डाउनलोड कर लें और न चाहें तो न करें। इसके फायदों को देखते हुए वह खुद ही लोकप्रिय हो जाएगा। हां, फायदों की जानकारी लोगों को जरूर दी जानी चाहिए थी। इसे लेकर गोपनीयता और संभावित निगरानी को लेकर चिंताएं पैदा हुई, जिनके पीछे भले ही कोई आधार नहीं रहा होगा, पर वे वाजिब थीं। संचार मंत्रालय ने अब बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए प्री-इंस्टॉलेशन को अनिवार्य नहीं बनाने का निर्णय लिया है।' मतलब यह भी नहीं है कि सरकार साइबर अपराधों को रोकने की अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो ले।

वस्तुत: यह साख का सवाल है। पिछले सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने देशभर से सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामलों की देशभर में जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। इसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो/ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटिजन को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। वस्तुत: यह मामला जागरूकता के अभाव की ओर इशारा करता है, साथ ही जनता और सरकार के बीच की दूरी को भी बताता है। कोई व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताकर जब फोन करता है तो सामने वाला डरता है। उसे लगता है कि किसी गलत मामले में उसे फंसाया जा सकता है। लोगों के मन में यह डर बहुत गहरा बैठा हुआ है। ठगों ने उसका ही दोहन किया है, अन्यथा जब आपने कोई गलती की नहीं है, तो डरने की जरूरत ही क्या है? इसके शिकार साधारण लोग ही नहीं, पढ़े-लिखे लोग भी हुए हैं।

ऐसे अपराधों को लेकर मीडिया में जितनी खबरें आई हैं, उतनी अपराधियों पर कार्रवाई की खबरें नहीं आई हैं। पिछले कई साल से यह काम चल रहा है। बड़े स्तर पर संगठित गिरोह इसका संचालन कर रहे हैं। इसका संगठित कारोबार अंतरराष्ट्रीय शक्ल ले चुका है। इसमें धोखाधड़ी वाले कॉल के माध्यम से लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। अपराधी सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और पीड़ितों को झूठे कानूनी आरोपों में फंसाने की धमकी देते हैं। इन घोटालों के साथ संगठित अपराध सिंडिकेट जुड़े हैं। इनमें वित्तीय संस्थानों का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी एप पर जनता का भरोसा नहीं होता। कोविड के दौरान 'आरोग्य सेतु' का देश की जनता ने भरपूर इस्तेमाल किया। वह डिजिटल स्वास्थ्य एप था, जो अब आरोग्य सेतु 2.0 के रूप में और बेहतर हो चुका है।

वह व्यापक वन हेल्थ एप है, जिसे स्वास्थ्य, कल्याण, चिकित्सा रिकॉर्ड, बीमा और परिवार की देखभाल सभी को एक ही स्थान पर प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह डिजिटल लॉकर जैसे उपयोगी ऐप भी हैं। बहरहाल, दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर को जारी प्रारंभिक आदेश में स्मार्टफोन निर्माताओं और आयातकों को नए फोन और पुराने फोनों में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से संचार साथी एप्लिकेशन पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि एप के कार्यों को अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसे साइबर सुरक्षा एप्लिकेशन बताया गया, जो उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी वाले कॉल, संदेशों और चोरी हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। बेशक इन सुविधाओं की नागरिकों को जरूरत है, पर उन्हें लगता है कि इनकी आड़ में सरकार गुपचुप उनकी निगरानी करने जा रही है। शायद अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने का तरीका उसने खोजा है। आदेश वापस लेने के पहले दिन में, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर आदेश में बदलाव के लिए तैयार है। सिंधिया ने संसद में कहा, '...अगर हमें प्राप्त फीडबैक के आधार पर आदेश में बदलाव करना पड़ा, तो हम इसके लिए तैयार हैं।' निगरानी संबंधी चिंताओं पर उन्होंने कहा, 'न तो जासूसी संभव है और न ही की जाएगी।'

एक दिन पहले सिंधिया ने स्पष्ट किया था कि एप वैकल्पिक है और उपयोगकर्ता इसे हटा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।' स्मार्टफोन निर्माताओं एपल और गूगल को, जिनके पास क्रमश: दो सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस और एंड्रॉइड हैं, इस आदेश को लेकर भी आपत्तियार्थी। इन कंपनियों का दृष्टिकोण है कि दुनिया में कहीं भी अपने उपकरणों में सरकारी एप्स प्री-लोड करने का इन फोन निर्माताओं का कोई इतिहास या मिसाल नहीं है। इसे लागू करने से परिचालन संबंधी चुनौतियां अलग से पैदा होंगी, क्योंकि इसके लिए उन्हें आईओएस और एंड्रॉयड में विशेष रूप से भारत के अनुरूप बदलाव करने पड़ सकते हैं। सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं ने एप को अनिवार्य बनाने से लोगों की निजता पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जताई थी, क्योंकि इसे प्री-लोड करने से पसंद और सहमति के सिद्धांत विफल हो जाते हैं, और भविष्य में 'कार्यात्मक विस्तार' की संभावना बनी रहती है।

गुड़गांव के पास इन जगहों पर घूमने का बनाएं प्लान

गुडगांव जिसे कई लोग गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं। यहां की नाइटलाइफ सिर्फ हरियाणा या दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर में फेमस है। दिल्ली के पास में होने के चलते यहां वीकेंड में घूमने के लिए दूर-दूर से लोग परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ पहुंचते हैं। गुड़गांव में अपने दोस्तों के साथ पार्टी से लेकर मस्ती-धमाल करने के लिए एक से एक बेहतरीन जगहें हैं। ऐसे में अगर आप वीकेंड में घूमने के साथ-साथ नाइटलाइफ एन्जॉय करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको गुडगांव/गुरुग्राम की कुछ जगहों के बारे में जानना जरूरी है जहां आप वीकेंड में घूमने से लेकर पार्टी करने तक का भरपूर मज़ा उठा सकते हैं। यहां सिर्फ 2000 रुपये में यादगार दिन बनाना बिल्कुल मुमकिन है। तो बजट की चिंता छोड़ें और अपने दोस्तों के साथ गुड़गांव के करीब कुछ शानदार जगहों पर एक खूबसूरत दिन बिताएं।

लेजर वैली पार्क

गुड़गांव में ही लेजर वैली पार्क स्थित है जहां हरियाली और मस्ती का संगम देखने को मिलती है। अगर आप प्राकृतिक खूबसूरती और शांति पसंद करते हैं तो गुड़गांव का लेजर वैली पार्क आपके लिए परफेक्ट है। सुबह-सुबह यहां जाएं, दोस्तों के साथ वॉक करें, फोटो क्लिक करें और खुद से जुड़ने का वक्त निकालें। यह पूरी तरह फ्री एंट्री वाला स्थान है। इस दिन साथ में ले जाएं घर से बना टिफिन और एक छोटा सा पिकनिक प्लान करें।

सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान

गुरुग्राम जिले में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दिल्ली से लगभग 50 किमी दूर है। इस स्थान को पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान माना जाता है। वैसे तो सर्दियों का मौसम यहां घूमने का सबसे अच्छा समय है लेकिन दोस्तों के साथ आप यहां आना चाहें तो पहले कुछ जानकारी और तैयारियां कर लें।

दमदमा लेक

गुड़गांव से दमदमा झील जाने के लिए सोहना रोड या गुरुग्राम-अलवर राजमार्ग का उपयोग कर सकते हैं। आप बस, टैक्सी या खुद गाड़ी से भी जा सकते हैं। झील के रास्ते में अरावली पहाड़ियों और ग्रामीण इलाकों के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही नौका विहार, रॉक क्लाइम्बिंग का आनंद भी ले सकते हैं। यह झीललोगों के बीच खूब लोकप्रिय है। अगर आप अपनी गुड़गांव यात्रा में कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो आपको इस जगह ज़रूर पहुंचना चाहिए। कहा जाता है कि यह झील प्रवासी पक्षियों की लगभग 190 से अधिक प्रजातियों का घर भी हैं। कई लोग शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए भी यहां पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इस झील का निर्माण अंग्रेजों द्वारा पानी को इकट्ठा करने के लिए किया गया था और आज यह एक पर्यटक स्थल बन चुका है।

फारुखनगर किला

हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित यह फारुखनगर एक ऐतिहासिक किला है। इसे 1732 में मुगल बादशाह फौजदार खान ने बनवाया था। इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए यह पर्यटन स्थल लोकप्रिय है। दिल्ली गेट नामक एक विशाल प्रवेश द्वार है। फारुखनगर किला गुरुग्राम शहर से लगभग 20 किमी दूर है। बजट में दोस्तों संग यहां हैंगआउट कर सकते हैं।

हंसना मना है

वाइफ- तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे? हसबेंड- नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वाइफ- कैसी गलतफहमी? हसबेंड- यही कि मैं सो रहा था।

रमेश - जरा देख तो बाहर सूरज निकला या नहीं? सुरेश - बाहर तो अंधेरा है। रमेश - अरे टॉर्च जलाकर देख ले कामचोर।

टीचर - बताओ मंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टूडेंट - बंदर, टीचर - किताब से देख कर बोला है न? स्टूडेंट - नहीं, मैंने तो आपको देख कर बोला।

टीचर - आज तुमने लेट आने का क्या बहाना ढूंढा? स्टूडेंट - मैडम आज मैं इतना तेज दौड़कर आया कि बहाना सोचने का मौका ही नहीं मिला।

पत्नी-मैं बचूंगी नहीं मर जाऊंगी। पति-मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी-मैं तो बीमार हूं लेकिन तुम किस लिए? पति-मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।

पत्नी- देखो बारिश का मौसम कितना हसीन है, तुम्हारा क्या प्लान है? पति- मेरा तो वही है 178 में 1 GB/day का 28 दिन के लिए। पत्नी बोली- घुस जा मोबाइल में।

कहानी | बैल और शेर

एक जंगल में तीन बैल रहा करते थे। तीनों आपस में अच्छे मित्र थे। वो घास चरने के लिए जंगल में एक साथ ही जाया करते थे। उसी जंगल में शेर की कई दिनों से इन तीनों बैल पर नजर थी। वह इन तीनों को मारकर खा जाना चाहता था। उसने कई बार बैलों पर आक्रमण भी किया, लेकिन बैलों की आपसी मित्रता के कारण वो कभी सफल नहीं हो पाया। जब शेर उन पर हमला करता था, तो तीनों बैल त्रिकोण बनाकर अपने नुकीले सींगों से अपनी रक्षा करते थे। लेकिन शेर कैसे भी करके उन तीनों को खाना चाहता था। शेर यह समझ गया था कि जब तक ये तीनों साथ रहेंगे, इन्हें मारा नहीं जा सकता है। इसलिए, उसने एक दिन इन तीनों को अलग करने के लिए एक चाल चली। शेर ने बैलों को अलग करने के लिए जंगल में एक अफवाह उड़ा दी। अफवाह यह थी कि इन तीनों बैलों में से एक बैल अपने साथियों को धोखा दे रहा है। बस फिर क्या था, बैलों के बीच इस बात को लेकर शक बैठ गया कि आखिर वो कौन है, जो हमें धोखा दे रहा है? एक दिन इसी बात को लेकर तीनों बैलों में झगड़ा हो गया। शेर ने जो सोचा था, वो हो गया था। अब तीनों बैल अलग-अलग रहने लगे थे। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। अब वो अलग-अलग होकर जंगल में चरने जाने लगे थे। बस शेर को इसी मौके का इंतजार था। शेर ने एक दिन उन तीनों बैलों में से एक पर हमला बोल दिया। अकेले पड़ जाने की वजह से वह बैल शेर का मुकाबला नहीं कर पाया और शेर ने उसे मार डाला। कुछ दिनों के बाद शेर ने दूसरे बैल पर भी हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। अब सिर्फ एक बैल बचा था। वह समझ गया था कि शेर अब उसको भी मार डालेगा। उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन जब वह जंगल में घास चरने गया था, तो शेर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। शेर की चाल पूरी तरह कामयाब हुई और उसने तीनों बैलों की दोस्ती तोड़कर उन्हें अपना शिकार बना लिया था।

7 अंतर खोजें

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष आय में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। जल्दबाजी न करें।

वृषभ पूजा-पाठ में मन लगेगा। कानूनी अड़चन दूर होगी। जल्दबाजी से हानि संभव है। थकान रहेगी। कुसंगति से बचें। निवेश शुभ रहेगा। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा।

मिथुन आय में निश्चितता रहेगी। शत्रुभय रहेगा। घर-परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। चोट व दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है।

कर्क प्रेम-प्रसंग में जोखिम न लें। व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। निवेश में सोच-समझकर हाथ डालें। शत्रु पस्त होंगे। विवाद में न पड़ें। प्रमाद न करें।

सिंह परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। स्थायी संपत्ति से बड़ा लाभ हो सकता है। समय पर कर्ज चुका पाएंगे। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न तथा संतुष्ट रहेंगे।

कन्या मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। समय की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। लाभ होगा।

तुला मेहनत अधिक व लाभ कम होगा। किसी व्यक्ति के उकसाने में न आएं। शत्रुओं की पराजय होगी। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। आय में निश्चितता रहेगी।

वृश्चिक जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। चिंता बनी रहेगी। कार्यसिद्धि होगी। निवेश लाभदायक रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ होगा।

धनु व्यापार मनोनुकूल लाभ देगा। जोखिम बिलकुल न लें। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे।

मकर बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। कारोबारी बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। निवेश में सोच-समझकर हाथ डालें। आशंका-कुशंका रहेगी।

कुम्भ व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। आय होगी। फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें। बजट बिगड़ेगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी।

मीन उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। शेयर मार्केट से बड़ा लाभ हो सकता है। संचित कोष में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। यात्रा लाभदायक रहेगी।

बॉलीवुड | मन की बात

मुझे कभी इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती : ऐश्वर्या राय बच्चन

ऐश्वर्या राय बच्चन रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 की ओपनिंग सेसेमनी में शामिल हुईं। यहां उन्होंने अपने लुक और स्टाइल से हमेशा की तरह लाइमलाइट लूटी। इसके अलावा यहां हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्ट्रेस ने अपने प्रोफेशनल फैसलों और इनसिक्योरिटी पर बात की। ऐश्वर्या राय ने इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया था। जिसमें वे दूसरे स्थान पर रहीं थी। इसके बाद उन्हें 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया और फिर दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम की 1997 की तमिल फिल्म इरुवर से एक्टिंग की शुरुआत की। जब ऐश्वर्या से इनसिक्योरिटी को लेकर सवाल किया गया तो एक्ट्रेस ने कहा, मुझे समझ नहीं आता। मुझे इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि यह मेरे बारे में एक बहुत असली बात है। इनसिक्योरिटी कभी भी ड्राइविंग फोर्स नहीं रही है। जो आसपास की बहुत सारी आवाजें आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर सकती हैं, और कभी-कभी चॉइस को आगे बढ़ा सकती हैं। यह कुछ ऐसा है, जो मेरे मैं कभी नहीं रहा। तो, शायद यह मेरे सभी करियर चॉइस के बारे में भी एक क्लैरिटी है। अनजाने में, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो मैंने शुरू से ही दिखाया। एक्ट्रेस ने कहा, मेरा मतलब है, अगर मैं किसी पेजेंट से आई थी, तो यह इस बारे में था कि जब मैं फिल्मों में आऊंगी तो बड़ा लॉन्च क्या होगा। मुझे याद है मणिरत्नम ने मुझसे कहा था, इरुवर असल में कोई आपके लिए लॉन्च फिल्म नहीं है। यह एक मूवी है, यह एक कहानी है, यह ऐश्वर्या को लॉन्च करने के बारे में नहीं है। मैंने कहा, वाह, यही वह मूवी है जो मैं करना चाहती हूं। बिल्कुल। क्योंकि यही वह मूवी है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती हूं।

19 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी फिल्म 'फोर मोर शॉट्स प्लीज'

चिंत सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के फाइनल सीजन का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए खुशखबरी है। सीरीज के फाइनल सीजन की रिलीज डेट का एलान हो चुका है। सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगारू अभिनीत सीरीज का दर्शक इसी महीने लुत्फ उठा सकेंगे।

प्राइम वीडियो ने साझा किया अपडेट

इंटरनेशनल एमी नॉमिनेटिड सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' को दुनियाभर के दर्शक 19 दिसंबर से देख सकेंगे। इस तारीख से सीरीज का प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर होगा। शुक्रवार को प्राइम वीडियो से एक पोस्ट शेयर कर रिलीज डेट पर अपडेट दिया गया है। इसके साथ कैप्शन लिखा है, आप ओजी गैंग की मीट-अप में आमंत्रित हैं।

सीरीज के इस फाइनल सीजन का एलान इस साल जुलाई में एक पोस्टर रिलीज के साथ किया गया था। बता दें कि इस सीरीज में आज की महिलाओं की जिंदगी के उतार-चढ़ाव को दिखाया गया है। सीजन 4 में शो की लीडिंग लेडीज

दामिनी, अंजना, सिद्दी और उमंग ये जानने वाली हैं कि उन्हें किसी और का नंबर वन बनने की जरूरत नहीं, बल्कि वो खुद अपनी लाइफ की हीरो हैं। क्योंकि खुशी कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है।

ये सितारे हैं सीरीज का हिस्सा

इस बार कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे और शो की फेमस गर्ल्स ट्रिप्स तो हैं ही। सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगरू के अलावा लीजा रे, प्रतीक बब्बर, राजीव सिद्धार्थ, अंकुर राठी और मिलिंद सोमन सरीखे सितारे भी नजर आएंगे। अरुणिमा शर्मा और नेहा पार्टी माटियानी द्वारा निर्देशित इस सीजन को देविका भगत ने लिखा है। इसके डायलॉग्स ईशिता मोइत्रा के हैं। हालांकि, अभी चौथे सीजन की रिलीज डेट जारी नहीं की गई है।

धुरंधर की हुई धुआंधार ओपनिंग, रिलीज होते ही तोड़े कई रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बड़े पर्दे पर आते ही ये गैंगस्टर-ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। रणवीर सिंह की फिल्म ओपनिंग डे पर बंपर कलेक्शन कर रही है और धड़ाधड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब तक धुरंधर ने ओपनिंग डे पर 2025 की कई फिल्मों के रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए हैं।

धुरंधर 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई इकलौती बॉलीवुड फिल्म है। ऐसे में फिल्म क्लैश से बच गई है और बॉक्स ऑफिस पर चौतरफा राज कर रही है। फिल्म को सिंगल रिलीज का फायदा मिला है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर 10.78 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। इसी के साथ इसने कई फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दे दी है।

धुरंधर ने ओपनिंग डे पर एक दर्जन से ज्यादा फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रणवीर सिंह की फिल्म ने इस साल रिलीज हुई फिल्म सन ऑफ सरदार 2 को मात दे दी है जिसने ओपनिंग डे पर 7.25 करोड़ की कमाई की। धुरंधर ने भूल चुक माफ (7.20 करोड़), परम सुंदरी (7.37 करोड़) और केसरी चैप्टर 2 (7.84 करोड़) के फर्स्ट डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा फिल्म ने दे दे प्यार दे 2, जाट, एक दीवाने की दीवानियत, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और सितारे जमीन पर जैसी फिल्मों को भी मात दे दी हैं।

धुरंधर ने इन फिल्मों को भी पछाड़ा

धुरंधर में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी अहम रोल में हैं। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने इन एक्टर्स की फिल्मों को भी मात दी है। धुरंधर ने संजय दत्त की फिल्म डबल धमाल (7.62 करोड़) के ओपनिंग कलेक्शन को पछाड़ दिया है। वहीं अर्जुन रामपाल की फिल्म हिरोईन (7.50 करोड़) और अक्षय खन्ना रेस (6.32 करोड़) भी धुरंधर से पीछे रह गई है। इसके अलावा धुरंधर ने आर माधवन की फिल्म केसरी चैप्टर 2 (7.84 करोड़) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

अजब-गजब | 21 तोपों की सलामी की परंपरा आज की नहीं 14वीं सदी की है

शांति का प्रतीक है 21 तोपों की सलामी, ज्योतिष और बाइबिल के अनुसार इसे माना जाता था शुभ

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं और शुक्रवार को वो भारत की राष्ट्रपति से राष्ट्रपति भवन में मिले। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 21 तोपों की सलामी देना देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर 21 तोपों की सलामी दी क्यों जाती है और इसका इतिहास क्या है? चलिए आपको बताते हैं।

21 तोपों की सलामी दुनियाभर में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान में से एक होती है। भारत में भी इसे बेहद प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। यह परंपरा भारत को ब्रिटिश शासनकाल से विरासत में मिली, और बाद में सभी कॉमनवेल्थ देशों ने इसे अपनाया। आज यह सम्मान राष्ट्रपति, राष्ट्रीय ध्वज और विशेष राज्य समारोहों में दिया जाता है। ब्रिटिश राज के दौरान भारत ने एक औपचारिक और विस्तृत तोपों की सलामी व्यवस्था विकसित की। स्वतंत्रता से पहले विभिन्न पदों के लिए सलामी का क्रम इस प्रकार निर्धारित था-

101 तोपों की सलामी

- ब्रिटेन के राजा/भारत के महाराज 31 तोपें- रानी, शाही परिवार के सदस्य, वॉयसराय, गवर्नर

जनरल। 21 तोपें- विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और उनके परिवार के सदस्य। 19 तोपें- सरकार प्रमुख, पुर्तगाल के गवर्नर जनरल, भारतीय राजदूत, फील्ड मार्शल रैंक के कमांडर-इन-चीफ। 17 तोपें- बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर, भारतीय प्रांतों के गवर्नर, फ्रेंच इंडिया के गवर्नर, राजनयिक, जनरल रैंक के सैन्य अधिकारी 'वेदांतु' और 'डेली ओ' की रिपोर्ट के अनुसार तोपों की सलामी की शुरुआत 14वीं सदी में मानी जाती है, जब तोपें पहली बार इस्तेमाल की गई थीं। एक तोप एक ही बार गोला दाग सकती थी, इसलिए जहाज़ों या किलों द्वारा सभी तोपें एक साथ दागना यह संदेश देने का तरीका था कि हमारी ओर से कोई खतरा नहीं है। शुरुआती वक्त में युद्धपोत 7 तोपों की सलामी देते थे। इसे ज्योतिषीय और बाइबिल से जुड़े महत्व के कारण शुभ माना जाता था। तटीय किले प्रतिउत्तर में तीन गुना गोलियां दागते थे, जिसके चलते कुल संख्या बनती थी 7 में 3 = 21। समय के साथ यह संख्या मानक बन गई और बाद में तीनों सेनाओं ने भी इसे अपनाया। समुद्री इतिहास बताता है कि जब युद्धपोत किसी जान-पहचान वाले बंदरगाह में प्रवेश करते थे, वे अपनी सभी तोपें दागकर यह साबित करते थे कि उनके पास हथियार नहीं हैं और शांतिपूर्ण उद्देश्य से आए हैं। इससे आधुनिक 21 तोपों की सलामी की नींव पड़ी।

इस नदी में बहता है खून सा पानी सच जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

दुनिया में कई ऐसी नदियां हैं जो अपनी साफ-सुथरी पानी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, कि एक ऐसी भी नदी है जहां खून जैसील लाल नदी बहती हो। पेरू में स्थित पुकामयु नदी एक ऐसी नदी है जो अपने लाल रंग के कारण काफी प्रसिद्ध है। दूर से देखने पर यह नदी खून जैसी दिखाई देती है। साथ ही इसे देख कर कई लोग इस नदी को डरावनी मानते है और काफी डर भी उनके मन में इस नदी को लेकर है। हालांकि, इस नदी को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।जो इस नदी को देख पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। पुकामयु नदी का पानी सच में खून की तरह लाल दिखाई देता है। इसे ब्लड फॉल्स या ब्लड रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, इस नदी का असली नाम पुकामयु है।

क्यों आता है खून जैसा लाल पानी...इस नदी का पानी लाल रंग का होने का मुख्य कारण इसमें आयरन की अधिक मात्रा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मानसून के दौरान नदी का पानी भूरे रंग में बदल जाता है। हर साल रेनबो माउंटेन विनीकुंका के पास स्थित इस नदी को देखने के लिए पर्यटक आते हैं, जहां हजारों लोग इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेते हैं। साथ ही इसके अलावा, कई फोटोग्राफर भी यहां की खूबसूरत तस्वीरें खींचने के लिए आते हैं।

राहुल-खरगे को न्योता न मिलने पर बवाल

» कांग्रेस ने उठाए सवाल भाजपा को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति भोज में आमंत्रित नहीं किया गया है। पुतिन दो दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को इस रात्रिभोज का निमंत्रण मिला है। बाद में, उन्होंने निमंत्रण मिलने की पुष्टि की और कहा कि वह ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगी। इस प्रकार, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्राध्यक्षों को औपचारिक रात्रिभोज के साथ सम्मानित करने की दीर्घकालिक परंपरा जारी रहेगी।

वहीं, पुतिन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण शिखर वार्ता से पहले राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के दौरान 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। पुतिन के इस दौरे पर पश्चिमी देशों की नजर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रूसी राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पहले बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री ने रूसी नेता को निजी रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया था। औपचारिक स्वागत के बाद, पुतिन राजघाट पहुंचे और वहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रूसी राष्ट्रपति कल शाम लगभग सात बजे नयी दिल्ली पहुंचे थे। वह चार साल बाद भारत की यात्रा पर आए हैं। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है।

पुतिन के सम्मान में भोज, थरूर आमंत्रित

मुझे विपक्ष के नेता को आमंत्रित न किए जाने की जानकारी नहीं : थरूर

थरूर ने कहा कि मुझे विपक्ष के नेता को आमंत्रित न किए जाने की जानकारी नहीं है, और मुझे यह भी नहीं पता कि निमंत्रण किस आधार पर जारी किए गए। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें आमंत्रित किए जाने पर गर्व है। सूत्रों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अवर महासचिव और व्यापक कूटनीतिक अनुभव वाले थरूर को रूसी कूटनीति के साथ उनके लंबे समय से जुड़े संबंधों को देखते हुए आमंत्रित किया गया है।

सांसद जयराम रमेश ने मोदी के ट्रंप के साथ संबंधों पर किया कटाक्ष

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंधों पर कटाक्ष किया। यह कटाक्ष अमेरिका की 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) के जारी होने के बाद किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई में बढ़े तनाव के बाद ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। यह पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया था जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता ने कहा कि व्हाइट हाउस द्वारा गुरुवार को जारी 33-पृष्ठ के दस्तावेज़ में इसके परिचय में और फिर पृष्ठ 8 पर दोहराया गया है कि ट्रंप ने आठ उग्र संघर्षों को सुलझाया जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुआ तनाव भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 2017 के रणनीति दस्तावेज़ की तुलना में पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में बदलाव आया है। 2025 की रणनीति में अमेरिका द्वारा अपने सहयोगियों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना, कड़े आतंकवाद-रोधी उपायों का आह्वान और इस्लामाबाद से अपने परमाणु शस्त्रागार का जिम्मेदाराना प्रबंधन करने का आग्रह करने का कोई ज़िक्र नहीं है।

चार साल में राज्य के लिए बहुत कुछ करना होगा : फारूक अब्दुल्ला

» बोले- एनसी की राह मुश्किल जनता हमारा साथ दे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) प्रमुख और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जनता से समर्थन की अपील की और माना कि पार्टी पिछले एक साल में लोगों के लिए कुछ खास हासिल नहीं कर पाई। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी संस्थापक शेख अब्दुल्ला की 120वीं जयंती पर बोलते हुए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने एक साल में लोगों के लिए कुछ खास नहीं किया, लेकिन हमारे पास विकास के लिए चार साल और हैं, और लोगों को हमारा समर्थन करना चाहिए और हमें मजबूत करना चाहिए। दिवंगत शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती थे।

फारूक और मुख्यमंत्री उमर ने हजरतबल के नसीम बाग स्थित उनके अंतिम विश्राम स्थल पर शेख को पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच, उमर ने घोषणा की कि सरकार ने एसआरओ-43 योजना का नाम बदलकर आरएएस कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कश्मीर प्रांत के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और अब तक 60 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आरएएस योजना के तहत, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत जम्मू में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब्दुल्ला ने कहा कि यह योजना, जिसे पहले एसआरओ-43 के नाम से जाना जाता था, अब आरएएस के नाम से जानी जाती है। इसके तहत, सरकार अपने सभी कर्मचारियों को आश्वासन देती है कि, ईश्वर न करे, यदि सेवाकाल के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी के तहत, कश्मीर प्रांत के लिए आदेश तैयार किए गए और 60 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया: केटी आर

» कांग्रेस के शासन में राज्य की आर्थिक हालत खस्ताहाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने शनिवार को तेलंगाना की गिरती राजस्व वृद्धि को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला और राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट में कहा कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने सीएजी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि तेलंगाना की राजस्व प्राप्तियां 2014 और 2023 के बीच 220 प्रतिशत बढ़कर 49,779 करोड़ रुपये से 1,59,349 करोड़ रुपये हो गईं। हालांकि, 2024-25 में यह वृद्धि घटकर -1.18 प्रतिशत रह गई, और 2025-26 के सात महीनों में राजस्व प्राप्तियां 94,555 करोड़ रुपये रहीं।

रेवंत ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने तेलंगाना को विफल कर दिया! तेलंगाना, जो कभी बीआरएस शासन के दौरान राजस्व वृद्धि चार्ट में सबसे ऊपर था, अब नकारात्मक दिशा में जा रहा है। सीएजी के अनुसार, 2014 और 2023 के बीच तेलंगाना की राजस्व प्राप्तियां 220 प्रतिशत बढ़ीं। (2014-15 में 49,779 करोड़ रुपये से 2022-23 में 1,59,349 करोड़ रुपये) हालांकि, 2024-25 में समान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि -1.18 प्रतिशत तक गिर गई, और 2025-26 में (सात महीनों के लिए), राजस्व केवल 94,555 करोड़ रुपये है। इससे पहले, केटीआर ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और उसे तेलंगाना की कहानी में स्थायी खलनायक बताया और राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केसीआर के प्रयासों के बिना, आज तेलंगाना का अस्तित्व ही नहीं होता। केटीआर ने तेलंगाना के लोगों द्वारा दिए गए बलिदानों और छह दशकों के दौरान कांग्रेस शासन द्वारा किए गए अन्याय को याद किया।

दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों पर ताला, मचा बवाल

» आप और बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाए आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक बंद करने की प्रक्रिया जारी है। अब 95 और मोहल्ला क्लीनिकों को बंद करने के लिए सूची जारी की गई है। इसको लेकर दिल्ली की सियासत में बवाला मच गया है। आप व भाजपा आमने-सामने आ गए हैं। बता दें स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के शून्य से 1.6 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्लीनिकों को बंद किया जाएगा। यह मोहल्ला क्लीनिक पोर्टा केबिन और किराये की इमारत में संचालित हो रहे हैं। इससे पहले एक किलोमीटर के दायरे वाले मोहल्ला क्लीनिक बंद किए गए थे।

मोहल्ला क्लीनिक बंद होने पर कार्यरत कर्मियों के बीच रोष है। इससे पहले सितंबर, अक्तूबर में भी क्लीनिक बंद किए गए थे। आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि इन 95 क्लीनिक को मिलाकर बंद होने वाले क्लीनिकों की संख्या 296 हो जाएगी। इससे लगभग 1100 से अधिक कर्मी बेरोजगार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 16 मई को जनता दरबार में वादा किया था कि सभी स्वास्थ्यकर्मियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा इसी मामले में कैट के भी 22 जनवरी 2026 तक कुछ कर्मियों के स्टे ऑर्डर हैं। जिनको निकाला नहीं जा सकता है। कर्मियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि समस्या दूर करे और उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में नियुक्त किया जाए।

सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज से वंचित कर रही : भारद्वाज

वहीं इसपर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 95 और मोहल्ला क्लीनिक बंद होने की आशंका पर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज से वंचित कर रही है, मेट्रो स्टेशनों और शॉपिंग मॉल में शराब के प्रीमियम शोरूम खोलने की तैयारी कर रही है। उनके अनुसार, सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी से पीछे हट रही है।

भ्रामक बयानबाजी और झूठ फैला रही आप : प्रवीण शंकर

भाजपा ने आप पर भ्रामक बयानबाजी और झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने कहा कि पिछले 18 महीनों में लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम स्तरों के चुनावों में हार के बावजूद आप नेता अब भी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ना बंद नहीं कर रहे। सौरभ लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दिल्लीवासी अब उनके दावों पर भरोसा नहीं करते। कपूर ने मोहल्ला क्लीनिक को छलावा बताते हुए दावा किया कि इन केंद्रों में डॉक्टरों की जगह कंपाउंडर दवा बांटते थे।

आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए शेफाली नामित

» मेंस खिलाड़ियों में एक भी भारतीय नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत की महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा को नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की रेस में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वह अकेली भारतीय हैं। विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में शेफाली वर्मा 87 रन तेजतर्रार पारी खेली थी। वहीं मैच में 2 विकेट भी चटकाई थी। वहीं मेंस टीम के लिए चुने गए तीन खिलाड़ियों में कोई भारतीय शामिल नहीं है।

प्रतीका रावल को चोट लगने की वजह से शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया था। शेफाली वर्मा के साथ इस अवॉर्ड की रेस में यूएई की कप्तान ईशा ओजा और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग भी हैं। इन दोनों ने बैंकॉक में हुई महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी में बेहतरीन खेल दिखाया था। ईशा ओजा ने टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाते हुए 137.50 के स्ट्राइक रेट से 187 रन बनाए और सात विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनीं। वहीं थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग 15 विकेट लेकर पूरे टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज रहीं। फाइनल मुकाबले में उनके चार विकेट बेहद अहम साबित हुए और उसी की बदौलत थाईलैंड ने खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष खिलाड़ियों की कैटेगरी में इस बार साउथ अफ्रीका के ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर, बांग्लादेश के लेफ्ट-आर्म स्पिनर तैजुल इस्लाम और पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को नॉमिनेट किया गया है। हार्मर ने हाल की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8.94 के बेहतरीन औसत से 17 विकेट झटके और दक्षिण अफ्रीका को भारत के खिलाफ 2-0 की जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस प्रदर्शन ने उन्हें उपमहाद्वीप की पिचों पर खेलने वाले सबसे सफल स्पिनरों में से एक बना दिया है।

सचिन तेंदुलकर के तीन बड़े रिकॉर्ड खतरे में!

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट इतिहास में सचिन तेंदुलकर का नाम सम्मान, उपलब्धियों और असंभव रिकॉर्ड्स का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब समय के साथ उनके कुछ बड़े रिकॉर्ड ऐसे खिलाड़ियों की पहुंच में आते दिख रहे हैं जो लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं। चाहे वनडे हो या टेस्ट, तेंदुलकर के ऐतिहासिक आंकड़ों के करीब अब कुछ दिग्गज बल्लेबाज तेज रफ्तार से पहुंच रहे हैं। भारत में खेले गए वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन तेंदुलकर 6976 रन के साथ अभी शीर्ष पर हैं, लेकिन विराट अब तक 6562 रन बना चुके हैं। वहीं कोहली ओवरऑल 84 शतक लगा चुके हैं। वह शतकों के शतक से 16 शतक दूर हैं। सिर्फ वनडे में नहीं, बल्कि टेस्ट में भी सचिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दबाव में है। सबसे ज्यादा टेस्ट शतकों (51) का। इस लिस्ट में जो रूट 40 टेस्ट शतक दर्ज कर चुके हैं।

महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व नेता प्रतिपक्ष ने डॉ. आंबेडकर को दी श्रद्धांजलि

» कांग्रेस अध्यक्ष खरगे व सोनिया गांधी ने भी किया याद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। देश आज भारत रत्न डॉ. बीआर आंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन कर रहा है। इसी बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा लिखा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर वे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को स्मरण करते हैं। उनकी दूरदर्शी सोच, न्याय और समानता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता तथा संवैधानिक मूल्यों ने भारत की विकास यात्रा को दिशा दी है।

वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस

अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व सोनिया गांधी ने भी उन्हें याद किया। बता दें कि डॉ. आंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इसी दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1956 में ही बाबासाहेब ने हिंदू धर्म की कुरीतियों और सामाजिक असमानताओं से दुखी होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध दर्शन के अनुसार परिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु के बाद पूर्ण मुक्ति, अर्थात सभी इच्छाओं, मोह-माया और सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त होना। यह सर्वोच्च अवस्था बहुत कठिन मानी जाती है और सदाचार व अनुशासित जीवन से ही प्राप्त होती है। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

बाबा साहब आगे भी हमारा मार्ग रोशन करते रहें : पीएम मोदी

एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने आगे कहा कि आंबेडकर ने पीढ़ियों को मानव गरिमा और लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी ने कामना की कि बाबासाहेब के आदर्श विकसित भारत के निर्माण में आगे भी हमारा मार्ग रोशन करते रहें।

आंबेडकर के संविधान की रक्षा करना राष्ट्रीय जिम्मेदारी : राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव आंबेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संसद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आंबेडकर के विचारों और संविधान की रक्षा करना एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। श्रद्धांजलि समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने बाबासाहेब आंबेडकर को एक महान राष्ट्रीय व्यक्तित्व बताया, जिनके विचार आज भी भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक ढांचे का मार्गदर्शन करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आंबेडकर जी एक आदर्श हैं। उन्होंने पूरे देश को रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें संविधान दिया। इसलिए, हम उन्हें याद करते हैं और उनके विचारों और संविधान की रक्षा करते हैं। हर भारतीय का संविधान खतरे में है। हम इसकी रक्षा करते हैं, नागरिक इसकी रक्षा करते हैं।

भाजपा इतिहास बदलने की कर रही साजिश : सोनिया

» कांग्रेस नेता का भाजपा पर तीखा हमला

» बोलीं- नेहरू की विरासत को नष्ट करने का प्रयास

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सोनिया गांधी ने भाजपा पर जवाहरलाल नेहरू की विरासत को विकृत करने और इतिहास को फिर से लिखने की सुनियोजित कोशिश का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने राष्ट्र की नींव को नष्ट करने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रयास स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान का विरोध करने वाली कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रेरित है।

कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को विकृत और अपमानित करने के प्रयासों की कड़ी आलोचना की और इसे इतिहास को फिर से लिखने और राष्ट्र की नींव को नष्ट करने का एक सुनियोजित प्रयास बताया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जवाहरलाल नेहरू की विरासत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए, सोनिया गांधी ने दावा किया कि उनका लक्ष्य देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को नष्ट करना है। राष्ट्रीय राजधानी स्थित जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की परियोजना आज सत्ताधारी

प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य है। उनका लक्ष्य केवल उन्हें मिटाना नहीं है, बल्कि वास्तव में उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को नष्ट करना है जिन पर हमारे राष्ट्र की स्थापना और निर्माण हुआ है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने कहा कि हम उनके (पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू) योगदानों के निरंतर विश्लेषण का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें बदनाम करने, विकृत करने, अपमानित करने और अपमानित करने का व्यवस्थित प्रयास अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य न केवल उन्हें एक व्यक्तित्व के रूप में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सर्वमान्य भूमिका और अभूतपूर्व समस्याओं से जूझ रहे एक स्वतंत्र राष्ट्र के नेता के रूप में उनके शुरुआती दशकों को कमतर आंकना है, बल्कि इतिहास को फिर से लिखने के स्वार्थी प्रयास में उनकी बहुमुखी विरासत को भी नष्ट करना है। उन्होंने इन प्रयासों को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान का विरोध करने वाली विचारधाराओं से जोड़ते हुए कहा कि ये कट्टरपंथी और

सोनिया गांधी पर मतदाता सूची मामले में नई याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई

सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में नाम शामिल करने की शिकायत को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा खारिज करने के बाद, शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जो 9 दिसंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित है। अदालत ने शिकायत को कानूनी रूप से असमर्थनीय और अधिकार क्षेत्र से बाहर माना था, जो अप्रमाणित मतदाता सूचियों पर आधारित थी और जिसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया था। सितंबर में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा खारिज की गई एक शिकायत, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल करने का आरोप लगाया गया था, को अब शिकायतकर्ता ने चुनौती दी है, जिसने सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। इस याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है, जिससे एक ऐसा मामला फिर से खुल जाएगा जिसे पहले ही शुरुआत में खारिज कर दिया गया था। सितंबर में अपने आदेश में, राउज़ एवेन्यू अदालत ने माना था कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ आपराधिक शिकायत कानूनी रूप से असमर्थनीय, तथ्यहीन और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने कहा कि सूचना देने वाले ने इस न्यायालय को ऐसा अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया था, जो कानूनन उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

क्रूर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से प्रेरित थे। गांधी ने कहा कि विश्लेषण एक बात है, लेकिन उन्होंने जो कहा, जो लिखा और जो किया, उसमें जानबूझकर गड़बड़ी करना दूसरी बात है और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वे कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने यह परियोजना शुरू की है? वे उस विचारधारा से ताल्लुक रखती हैं जिसकी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और हमारे संविधान के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी।

डीके शिवकुमार को ईओडब्ल्यू का समन कांग्रेस ने जताई आपत्ति

» बोले उपमुख्यमंत्री- सब कुछ साफ है फिर क्यों जांच

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी नोटिस पर आश्चर्य व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि यह स्थिति उनके लिए अप्रत्याशित थी, खासकर तब जब उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सभी आवश्यक विवरण पहले ही उपलब्ध करा दिए थे और उन्हें नोटिस भी दे दिया था। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, यह मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला है। मैंने ईडी को सारी जानकारी दे दी है। ईडी ने मेरे भाई और मुझे भी तलब किया है। हमने सभी को नोटिस दिया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह हमारी संस्था है। हम कांग्रेसियों ने भी संस्था का समर्थन किया है... इसमें लुका-छिपी जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ साफ है। मुझे नहीं पता कि ईडी द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद भी पुलिस को मामला दर्ज करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी। हम इस मामले को उठाएंगे और अदालत में लड़ेंगे। डीके शिवकुमार ने नेशनल हेराल्ड मामले की जाँच में उत्पीड़न का आरोप लगाया और दावा किया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके समर्थकों को निशाना बनाने के लिए कथित तौर पर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह उत्पीड़न है... यह हमारा पैसा है। हम टैक्स चुकाकर इसे किसी को भी दे सकते हैं। इसमें कुछ भी शामिल नहीं है। पीएमएलए का मामला पहले ही खत्म हो चुका है।

'इस मामले को अदालत में उठाएंगे और लड़ेंगे'

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपपत्र दाखिल कर दिए जाने के बाद, पुलिस को अलग से मामला दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, शिवकुमार ने कहा कि वह इस मामले को अदालत में उठाएंगे और लड़ेंगे।

जामनगर में आप विधायक गोपाल पर फेंका जूता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जामनगर। गुजरात के जामनगर में जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया पर किसी ने जूता फेंक दिया। जूता फेंकने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। इस घटना के बाद जनसभा में हंगामा मच गया। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आप कार्यकर्ताओं ने भी आरोपी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटा।

गोपाल इटालिया गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट से आप के विधायक हैं। उन्होंने जामनगर में बाइक रैली और जनसभा का आयोजन किया था। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने उनपर हमला कर दिया। इस घटना के बाद राज्य का सियासी पारा आसमान छूने लगा है।

इंडिगो की मनमानी पर भड़कीं सांसद सुप्रिया सुले

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद ने कहा - सरकार संसद में जवाबदेही तय करे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को इंडिगो की उड़ानों में हालिया व्यवधान की कड़ी निंदा की और भारत सरकार से संसद में एक आधिकारिक बयान जारी करने और मामले की जाँच शुरू करने का आग्रह किया।

एनसीपी-एससीपी सांसद ने यात्रियों को हो रही लंबे समय से हो रही असुविधा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इंडिगो के साथ जो हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। भारत सरकार को संसद में एक आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए और जाँच होनी चाहिए... आप देख सकते हैं कि पिछले दो

दिनों से क्या स्थिति है। भारत सरकार ने आज तक कोई बयान जारी नहीं किया है... मुझे उम्मीद है कि सोमवार को भारत सरकार इंडिगो के बारे में देश और संसद को जवाब देगी। सुले ने विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि किसी एक एयरलाइन का प्रभुत्व अर्थव्यवस्था, व्यवसाय और उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर चार-पाँच एयरलाइंस होतीं, तो यह स्थिति न होती। इसलिए, प्रतिस्पर्धा अच्छी है और ग्राहक ही राजा है। किसी एक एयरलाइन का एकाधिकार किसी भी अर्थव्यवस्था, देश या व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है। इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण के कारण देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो की ओर से लापरवाही, अनुत्तरदायी व्यवहार और कर्मचारियों की कमी की कई शिकायतों के कारण कई यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। सुले ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन किया कि संविधान खतरे में है और कहा कि यह वास्तव में सच है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा- समस्याओं के प्रति पूरी तरह सतर्क

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों, विशेष रूप से इंडिगो को, उड़ान कार्यक्रम में गंभीर व्यवधान को दूर करने और बिना किसी देरी के सेवाओं को स्थिर करने के लिए तुरंत उपाय लागू करने का निर्देश दिया है। जनता की समस्याओं का समाधान करने और विशेष रूप से इंडिगो पर सेवा स्थिरता बहाल करने के लिए दो आदेश जारी किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सतर्क है और सभी हितधारकों के साथ लगातार परामर्श कर रही है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। महाराष्ट्र कार्यालय :- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in | RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।